•देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना।

राहुल गांधी ने की गहलोत की योजना की तारीफ: कहा- बेरोजगारी दूर करने राजस्थान सरकार लाई है इंदिरा-गांधी शहरी रोजगार योजना

जयपुर 3 दिन पहले

Rajasthan news : राजस्थान सरकार की ओर से इसी साल बजट में पेश की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना " को देशभर में लागू करने की मांग की है। राहुल का कहना है कि इस स्कीम के जरिए बेरोजगारों को एक बड़ा फायदा होगा।

Rahul gandhi ashok gehlot

हाइलाइट्स

- राहुल गांधी ने की "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना " की सिफारिश
- राजस्थान सरकार की इस योजना को देशभर में लागू करने की रखी मांग
- राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस योजना को लागू करने की मांग रखी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan CM Ashok Gehlot) ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme) के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा-निदेशों को मंजूरी दे दी है. सीएम गहलोत ने कहा है कि स्थानीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्यों का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा, योजना में अनुमत कार्य करवाने के लिए राज्य/जिला/निकाय स्तर पर समितियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत और निष्पादित कराया जाएगा.

मनरेगा मजदूरों को 15 दिन में मिलेगा पैसा

सीएम गहलोत ने कहा कि सामान्य कार्य स्वीकृत और निष्पादित कराने की सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 होगा. वहीं विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए सामग्री लागत और पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75:25 होगा. अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा के तहत 15 दिनों के अंदर मजदूरों के बैंक खातों में कार्यों का भुगतान कर दिया जाएगा. गहलोत ने कहा कि इसके अलावा योजना में शिकायतों के निवारण एवं सोशल ऑडिटिंग के प्रावधान के साथ-साथ श्रमिकों को कार्यस्थल पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

निकाय स्तर पर एक योजना पर काम-सीएम

सीएम ने कहा कि, योजना को चलाने के लिए स्थानीय निकाय विभाग या निकाय के स्तर पर एक योजना पर काम किया जाएगा, जिसमें विभिन्न अधिकारियों/कर्मियों को प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त किया जाएगा. आपको बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी. उसी तर्ज पर यह योजना शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.

क्या है योजना

गहलोत ने राज्य के बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के लिए रोजगार देने की घोषणा की थी. इस महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार हर साल 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी.